Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक स्फेयर) के मायने

विनीत कुमार सिन्हा, Ph. D.

राजनीति विज्ञान विभाग, पी जी डी ए वी महाविद्यालय सांध्य, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

tobinni@gmail.com

Abstract

पब्लिक स्फेयर अपने आप में एक महत्वपूर्ण विमर्श है। यहां वाद है, विवाद है, नये विचार हैं। चूंकि यह एक स्फेयर है इसलिए यहां आने- जाने की सबके लिए अनुमति भी है अर्थात् प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त स्पेस और अवसर है। पब्लिक शब्द के होने से यह आधिकारिक नहीं हो जाता, यह निजी क्षेत्र है परन्तु विमर्श के विषय हमेशा सर्व हित का होता है। वाद-विवाद का विषय इसलिए भी है कि यहां हर विचार का स्वागत है, हर अभिव्यक्ति की उतनी ही इज्जत है। संकल्पना के रूप में सर्वप्रथम पब्लिक स्फेयर शब्द का व्यवस्थित विश्लेषण हेबरमास की लेखनी में आयी है। इनका कहना है कि आधिकारिक क्षेत्र में जिनकी न बात सुनी जाती हो और न ही उन्हें किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व मिलता हो, तो यह पब्लिक स्फेयर उन्हें वह सभी अवसर देता है जिसके द्वारा अपने को अभिव्यक्त कर सके। हालांकि नैंसी फ्रेजर, बेरेफ्ट, प्रो नीरा चंडोक ने इस क्षेत्र की सीमायी पहलू को जरूर छुआ है। यह सीमा जेंडर संबंधित, भाषा से संबंधित, सही लक्ष्य तक न पहुंच पाने जैसी इसकी मजबूरी के संदर्भ में हो सकता है। भारत के संदर्भ में माना यह जाता है कि यह क्षेत्र अपने दो अवधारणाओं के साथ विकसित हुई। रजनी कोठारी से लेकर आंद्रे बेते तक के बहस को हमने इसमें शामिल किया है। फिर ऐसे क्षेत्र से विकसित हुए सामाजिक संस्थाओं के व्यवहारिक पक्ष पर भी बिहार के ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रहे 'अदिथि' के संदर्भ में इस विमर्श को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अदिथि एक गैर-सरकारी संस्था होते हुए भी न केवल अपने को एक मॉडल के रुप में विकसित किया है बल्कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ सशक्तिकरण का एक उदाहरण के रूप में खुद को प्रस्तुत भी किया है।

की- वर्ड्स: *पब्लिक स्फेयर, सामाजिक हित, सशक्तिकरण, आय जनन, सामाजिक संस्थाएं, लोकतांत्रीकरण, नागरिक समाज, प्रतिनिधित्व*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना:

निरंतर सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता और प्रासंगिकता पर बात करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र एक संकल्पना के रूप में पहले पहल हेबरमास की लेखनी में विकसित हुई है। इससे आशय क्या है? इसके क्या मायने हैं? हेबरमास कहते हैं कि यह सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां जनमत बनते हैं। यहां सभी तरह के नागरिकों की पहुंच होती है चाहे वह किसी भी विशेषज्ञता से युक्त हो। मतलब यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहां आने वाले लोग प्राइवेट होते हैं लेकिन विमर्श एवं चर्चा का विषय सार्वजनिक स्वभाव का होता है। ऐसे में यहां एक सार्वजनिक निकाय की स्थापना हो जाती है। अर्थात यहां के लोग किसी पेशेवर की तरह व्यवहार नहीं करते जैसा कि प्राइवेट स्फेयर में होता है। संवैधानिक व्यवस्था द्वारा निर्मित किसी अधिकारीतंत्र के सदस्यों की तरह भी इनका व्यवहार नहीं होता। यहां केवल अबाधित तरीके से जनता के हितों को लेकर आपसी विचार विमर्श और एक दूसरे को परामर्श देने का काम करते हैं। यह सार्वजनिक निकाय सभा और संस्थाओं के निर्माण

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इससे विमर्शीय विचारों को अभिव्यक्त तथा उसका प्रकाशन भी संभव हो पाता है। सार्वजनिक क्षेत्र को आधुनिक समाज के एक ऐसे रंगशाला के रुप में देख सकते हैं जहां विमर्श और बातचीत द्वारा राजनीतिक भागीदारी संभव होता है। आशय यह हुआ कि यह सामाजिक जीवन का एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है जहां जनमत का निर्माण होता रहता है।

हेबरमास आगे लिखते हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक सत्ता के क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच मध्यस्थता करता है। निजी क्षेत्र में वस्तु और सामाजिक श्रम का विनिमय होता रहता है जबकि सार्वजनिक सत्ता के क्षेत्र में राज्य या पुलिस-प्रशासन तथा रूलिंग क्लास शामिल होता है। सार्वजनिक क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों के बीच का संकर(Crossed) है जो जनमत निर्माण द्वारा राज्य को सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़े रखता है। ऐसे में यदि यह क्षेत्र संवाद निर्माण के साथ उसके प्रसारित करने हेतु जिम्मेदार है तो स्वाभाविक रूप से इस स्फेयर में राज्य की आलोचना भी संभव है। अतः यह किसी भी तरीके से बाजार विनिमय के रुप में विकसित नहीं हो पाता, यहां कोई वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक विषयों पर वाद- विवाद और विचार विमर्श होता रहता है। यहां बने जनमत से सरकार की वैधता बनती बिगड़ती है।

हेबरमास के अनुसार पब्लिक स्फेयर के उद्भव और विकास में तीन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रिटेन की कॉफी हाउस, फ्रांस का सैलून तथा जर्मनी की वैसी संस्कृति जो डीनर पार्टी से निकली हो या फिर एक टेबल पर आपस में लोग विचार विमर्श करते हैं, इनके मिला जुला कारकों से पब्लिक स्फेयर का निर्माण हुआ है। इनका कहना था कि भले ही इनकी सदस्यों की संख्या, संरचना, उनके स्तर, विमर्श आरंभ करने के तौर तरीके, वाद विवाद का माहौल एवं विषयों के प्रति रूचि में भिन्नता हो सकती है लेकिन ये सभी ऐसे विमर्श को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते रहते हैं।

हेबरमास के इस पब्लिक स्फेयर को नैंसी फ्रेजर ने भेदभाव करने और प्रभुत्व प्रवृत्ति वाला बताया है। उनका कहना है कि विशेष जेंडर, सामाजिक स्थिति, प्रजाति एवं संपत्तिशाली वर्ग द्वारा नियंत्रित होने वाला यह क्षेत्र है। इसी तरह बेरेफ्ट (Bereft) मानते हैं कि यह क्षेत्र किसी निश्चित वर्ग के हितों को तो पूरा कर सकता है लेकिन सभी लोगों को ऐसे क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं मिल पाता और यह कोई विकास का प्रारूप भी नहीं देता। प्रत्येक क्षेत्र अपने में मौलिक और अलग होता है, जैसे- मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ, साहित्य, कला आदि। इसी कड़ी में नीरा चंडोक कहती हैं कि अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपिंस या भारत में होने वाले तमाम ऐसे क्षेत्र के निर्माण के प्रयास समाज के विशिष्ट वर्ग- वकील, विश्वविद्यालय शिक्षक, डॉक्टर या अन्य प्रोफेसनल्स द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। आगे उनका मानना है कि हासिए पर जा चुके किसानों की दुर्दशा हो या फिर अकेलेपन का शिकार हुए आदिवासी हो,जो अपनी स्वतंत्रता और हक की लड़ाई के लिए संघर्षरत है, इस क्षेत्र में अपने प्रवेश के लिए अभी भी प्रयासरत ही है। यही वजह है कि यह क्षेत्र और यह वर्ग अप्रतिनिधित्व ही बना हुआ है। इसी वजह से प्रो चंडोक की स्पष्ट मान्यता है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील आंदोलन को न केवल राज्य सत्ता से बल्कि शक्तिशाली नागरिक

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समाज से भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रो चंडोक हेबरमास के भाषायी सीमा की ओर भी इशारा करती हैं। वे कहती हैं कि ऐसे किसी क्षेत्र में प्रभुत्वशाली या विशिष्ट वर्गीय भाषा इनकी स्वीकार्यता के स्तर को कम कर देता है। हासिए पर रह रहे लोगों की विशिष्टवर्गीय भाषा होने की वजह से ज्ञान निर्माण एवं विमर्श में सहभागिता नहीं हो पाती। वहां सभी की आवाज न तो सुनी जाती है और न ही वहां तक पहुंच ही संभव हो पाता है। ऐसे में उनकी संस्कृति, रहन- सहन, खान -पान, एवं अन्य आवश्यकताओं सहित उनकी परेशानियों पर विमर्श तक नहीं हो पाता। अपनी विशिष्ट भाषा के माध्यम से खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए पब्लिक स्फेयर पर विमर्श एक सोची समझी रणनीति है।

पब्लिक स्फेयर पर होने वाले विमर्श से स्पष्ट है कि वह विमर्श, चर्चा और वाद- विवाद से संबंधित एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां नागरिक आपस में सामान्य हितों पर खुलकर बात रखते हैं। 'डेमोक्रेसी इन अमेरिका(1969)' में टाकविल कहते हैं कि ऐसा समाज या इसकी वजह से बनने वाली संस्थाएं उन्हें अपनी बात रखने का विकल्प देता है जिसे व्यवस्था ने अभी तक नहीं दिया है। यहां नागरिकों को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना मिलती है और सार्वजनिक विषयों के मुद्दे पर विमर्श में सभी शामिल होते हैं। ऐसे में यह क्षेत्र या संस्थाएं भागीदारी का समुचित अवसर प्रदान करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ -साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाती है। हम ऐसे भी कह लें कि यह समाज या क्षेत्र राज्य की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व देने वाली है और लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाती है। ऐसी कोई भी संभावना लॉक और मोंटेस्क्यू के अध्ययन में अनुपस्थित है। इससे यह भी स्पष्ट हो पाया कि यह न केवल नागरिकों की क्षमता बढ़ाती है बल्कि उनके सिविक वर्च्यू के विकास में भी सहायक है। यही वजह है कि ऐसी संस्थाएं सक्रिय, आत्मनिर्भर और विमर्शी नागरिकों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही ऐसी संस्थाएं शासन के एक वैकल्पिक प्रारूप के रूप में सहायक भी हो सका है। जहां राज्य अपने को सीमित पाता है वहां यह एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि टाकविल यह मान लेते हैं कि ऐसी संस्थाएं राज्य की अपेक्षा समस्या समाधान में अधिक उपयोगी होता है। टाकविल यहां पर सबसिडेरिटी(subsidarity) के तर्क द्वारा शासन प्रक्रिया में संस्थाओं की उपयोगिता जैसी संकल्पना को शामिल करते हैं। इससे सामूहिक कारवाई के साधन एवं क्षेत्र द्वारा समस्याओं की प्रकृति और क्षेत्र के साथ अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

टॉल्कट पार्संस ऐसे किसी भी क्षेत्र या संस्था या फिर समाज को संस्थात्मक संबंधों के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका मानना है कि यह सामूहिक रूप से निर्णय लेने और उसके क्रियान्वयन का क्षेत्र है। ऐसे में यहां समावेशी नागरिकों का विकास संभव हो पाता है। इस वजह से इसने राज्य के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक विषयों में सहभागिता के अधिकार और व्यक्ति के कल्याण के प्रति लोगों का ध्यान खींचा है। इस संबंध में पार्संस संस्थात्मक संबंधों में स्वैच्छिकता को बढ़ाने के लिए भी इसे ही जिम्मेदार मानते हैं अर्थात सदस्यों की स्वीकार्यता

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

एवं उनके बने रहने को लेकर है। इनकी भूमिका संबंधों, विभिन्नता एवं शक्ति के संसाधनों को बहुल बनाने में महत्वपूर्ण रही है। यह सहमति, साझे लक्ष्य तथा मूल्यों के प्रति सामूहिकता को लेकर एक मजबूत संबंधों के प्रति आग्रह करता है। पार्सस एक और तर्क देते हैं कि यह क्षेत्र प्रक्रिया विकास को भी लेकर महत्वपूर्ण है। समाज में यदि विभिन्नताएं हैं तो वह निर्भरता को एक स्थान पर केन्द्रीकृत नहीं होने देता अर्थात निर्भरता के क्षेत्र को भी बहुलवादी बना देता है। इससे निर्णय निर्माण के साधन की प्रक्रिया का विकास संभव हो पाता है।

भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो ऐसी संस्थाएं अपनी दो अवधारणाओं के साथ विकसित हुई है। पहली, राज्य के विकल्प एवं विरोध में है। यह राज्य एवं भारतीय दलीय व्यवस्था के समान रूप से असंवेदनशीलता की वजह से पूरे देश भर में फैल गया। ऐसे में गैर -सरकारी एवं गैर- दलीय संस्थाएं अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा राज्य के सत्तावादी और बढ़ते शक्ति को सीमित करती हुई प्रतीत होती है। दूसरी, अवधारणाएं आंद्रे बेते द्वारा विकसित हुई है। इन्होंने ऐसे क्षेत्र या समाज की पहचान संस्थाओं के समुच्चय द्वारा व्यक्ति और राज्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका के रूप में किया है। इस तरह की मध्यस्थ संस्थाएं पहले से ही सभी समाज में उपस्थित रहती है। लेकिन जिस समाज की बात यहां हो रही है वह सबके लिए खुला एवं धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का है।

पहली अवधारणा से आशय यह निकल रहा है कि राज्य इतने समय बीत जाने के बाद भी अपने घोषित वायदों को पूरा करने में असफल रहा है, इसलिए इसे विकल्प और विरोधी बताया जा रहा है। ऐसा होने से यहां जैसा कि प्रो चंडोक का मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर सक्रियता और जन आधारित राजनीतक आंदोलन इसलिए प्रभावित हुए हैं क्योंकि प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है। इसी वजह से राज्य शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र के रूप में बुद्धिजीवियों द्वारा राजनीतिक समाज की जगह इस तरह के नागरिक आधारित खुले समाज को स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि 80 के दशक में कई सामाजिक आंदोलन शुरु हुए- पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, खाद्य सुरक्षा, काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसे आंदोलन इसी सार्वजनिक क्षेत्र या समाज के द्वारा आरंभ हुआ। ऐसा नहीं कि ऐसे क्षेत्र के नाम पर केवल आंदोलन ही शुरू हुए जो राज्य के विरूद्ध या राज्य के समक्ष जोरदार मांग के रुप में आया बल्कि समाज के हाशिए पर रह रहे या समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा ढकेल दिए गए ऐसे समुदाय के सशक्तिकरण तथा उनके उत्थान के लिए भी जोरदार तरीके से कोशिश देखने को मिलती है। इस संबंध में बिहार में इसी दशक में आरंभ हुए 'अदिथि' के प्रयासों और कार्यों को हम देख सकते हैं। वैसे तो इस तरह के भागीरथ प्रयास करने वाली संस्थाएं अनेकों हैं परन्तु मैं यहां अपने रूचि के अनुसार 'अदिथि' के बारे में लिखना चाहूंगा।

मूल रूप से चेन्नई की रहने वाली श्रीमति विजी श्रीनिवासन 1988 में बिहार के पटना में अदिथि नाम से एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना करती है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण महिला से संबंधित है जिनके पास संसाधन का पर्याप्त अभाव है। यह उनके विकास में मदद के लिए समर्पित एक महिला आंदोलन है अर्थात अदिथि एक ऐसी महिला विकास का आंदोलन है जो महिला द्वारा महिला की और महिला के लिए है। सहयोगी के रूप में आर जे

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

राव एवं गोपाल प्रसाद सिंह उनके इस मुहिम साथ होते हैं। इनका उद्देश्य यह होता है कि समाज के कमजोर वर्ग विशेष रुप से महिलाओं के आर्थिक- सामाजिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को कैसे मजबूत किया जाय। ADITHI से तात्पर्य एग्रीकल्चर, डेयरी, इंडस्ट्री (स्माल), टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्री प्लांटेशन, हैंडीक्राफ्ट, हॉर्टीकल्चर, हैंडलूम, इंटेगरेटिंग पूअर रूरल वूमेन इन आल दीज सेक्टर से है। दरअसल ये इनका एक संक्षिप्त नाम है ADITHI. इसके लिए अदिथि द्वारा चुने गए बिहार के पांच जिलों- मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद और दुमका(अब झारखंड राज्य का भाग है) में इनके द्वारा किए कार्यों की समीक्षा और विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे।

इन्होंने जो काम करना आरंभ किया, उसके लिए उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जिससे उनकी सामुदायिक भागीदारी बढ़ सके, सामाजिक बुराईयों को कैसे नष्ट किया जाय यह बताया, उनपर होने वाले हिंसा के प्रति सचेत किया, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु आर्थिक उद्यमशीलता पर ट्रेनिंग के साथ उनके लिए आर्थिक गतिविधि के अन्य विकल्पों के बारे में बताया और प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का भी काम किया। साथ ही, यह भी मानना है कि गरीबी और अशिक्षा विशेषकर महिलाओं में उच्च जन्म-दर को बढ़ाता है, निरक्षरता गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को हतोत्साहित करता है, गुणवत्तापूर्ण जीवन, रोजगार, आय जनन गरीबी दूर करने में अहम भूमिका निभाती है।

इस दृष्टिकोण और उद्देश्य के साथ अदिथि आगे बढ़ती है। बिहार में काम कर रहे अन्य संगठनों जैसे- इमामी मूरमी, सेवा मिथिलो,तिलोथू महिला मंडल, रोहतास, महिला विकास सहयोग समिति, ग्राम सभा सेवा संस्थान आदि के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाते हुए स्पेयर हेड टीम का गठन किया गया। इस टीम में वैसी युवा महिलाओं को शामिल किया गया जो विशेष रूप से डेयरी, कृषि, सेरीकल्चर, हैंडलूम जैसे कार्यों में दक्ष थे। इन लोगों ने अलग अलग कामों के लिए अलग टीम लीडर को लगाया। इस तरह से एक एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हेड की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के साथ उनके बीच में रहकर उनमें यह विश्वास पैदा किया कि विकास कार्य के लिए और उसमें तीव्रता लाने के लिए आपकी भागीदारी होना कितना महत्वपूर्ण है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने अदिथि क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग कार्यों को वर्गीकृत किया, जैसे कि मधुबनी में मत्स्य पालन, मुजफ्फरपुर में डेयरी, कृषि, पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने हेतु प्रयास और ग्रामीण उद्योग, दुमका, देवघर, पलामू, कटिहार और नालंदा में वनीकरण, मिट्टी संरक्षण, जनजाति कल्याण, सीतामढ़ी, पटना, दुमका, मुजफ्फरपुर में हैंडीक्राफ्ट और ऋण की व्यवस्था, पटना, सीतामढ़ी में एड्स को लेकर जागरूकता अभियान, पटना, सीतामढ़ी,कटिहार, पूर्णिया में भ्रूण हत्या को रोकने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी सहायता देने जेसे विषयों पर अपने आप को फोकस करना आरंभ किया।

इसका असर भी हुआ। मधुबनी जिले के रियाम गांव में एक मत्स्य महिला ग्रुप का गठन कर सरकारी विभाग जैसे कि डी डी सी से बातचीत कर ग्रामीण तालाबों की संख्या बढाने पर काम करना शुरु हुआ। परिणामस्वरूप

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पनहर प्रखंड में दो तालाब, जहानाबाद में 15 तालाब और मधुबनी जिले में अलग अलग जगहों पर लगभग बीस तालाब खोदे गए। इनमें एक मानिसू पोखर जो 28 एकड़ भूमि में फैला था, बिहार के इतिहास में किसी संस्था को सरकारी प्रयास से इतना बड़ा पोखर मिलना ऐसी पहली घटना थी। इसमें मछली पालन और उत्पादन का कार्य अच्छे से होने लगा। यहां पर मछली माफिया से जूझना भी पड़ा लेकिन माफियाओं की पत्नि से बात कर उन्हें ही अपने अपने माफिया पति को समझाने की ज़िम्मेदारी दे दिया। इतना ही नहीं, अदिथि ने उन माफिया के पत्नि को अपने मुहिम में भी शामिल कर लिया। इस तरह रास्ते में आने वाली हर तरह की बाधाओं को बिना पुलिस प्रशासन के बातचीत और विमर्श द्वारा सुलझा लिया गया। फिर आगे बढ़ते हुए मत्स्य महिला सहकारिता एवं मछली बाजार को भी विकसित किया। इस प्रयास में श्रीमती विजी श्रीनिवासन और गंगिया मां का विशेष योगदान रहा है।

कृषि कार्य के लिए सहकारिता संचालन, प्रबंधन और तकनीकि जानकारी पर बल दिया जाना जरुरी था। महिला सदस्यों को ट्रैक्टर चलाना सिखाया, सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया गया, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयों के लिए फंड की व्यवस्था भी हुई। हैंडीक्राफ्ट के संबंध में हरित कला, खतवा, मूसरा महिला विकास समिति को सौंपे गए। व्यवसायीकरण के उद्देश्य हेतु 'सुजनी' के नाम से अपना एक उत्पाद आरंभ किया हुआ। 'खतवा' ऐसे फेब्रिक से बनाए गए जो पर्यावरण मित्र भी था। इस वजह से यह संस्था अपने उत्पादों की प्रदर्शनी अमेरिका और यूरोप में कर पाने में सफल भी हुआ।

आदिवासी महिलाओं के लिए इनका पहला प्रयास यह रहा कि उनके आय के स्रोतों का पता लगाया जाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। उन्हें तकनीक एवं वित्तीय सहायता दिलाना भी इनके एजेंडे में बहुत ऊपर था। इस कार्य के लिए इन्हें इग्नू विश्वविद्यालय का काफी सहयोग मिला। साथ ही, लड़कियों और उनके अधिकारों पर काफी काम हुआ है। इसमें शक्तिवर्धिनी, बाल महिला कल्याण, महिला विकास केन्द्र जैसे संगठनों ने अदिथि को काफी सहयोग किया है। इसके अंतर्गत लड़कियों को सामाजिक संरचना की समझ, लिंग आधारित भेदभाव, परिवारों में लड़कियों की महत्ता, शारीरिक संरचना एवं सेक्स आॅर्गन संबंधित जानकारी देना, हिंसा ,बलात्कार और उससे जुड़ी कानूनी जागरूकता, मुख्य कार्य रहे। रेड लाईट एरिया में कार्य करने वाली महिलाओं की बेटियों को जो छोटी उम्र की थी, उन्हें पेंटिंग, सिलाई, बैग बनाने जैसे कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया गया। मुजफ्फरपुर और बेतिया जिले में इस कार्य को बेहतर ढंग से सफलतापूर्वक किया गया है। इन बच्चों को दिल्ली स्थित निफ्ट जैसी संस्थाओं से भी कौशल विकास के लिए सफलतम प्रयास हुआ है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने में इनकी भूमिकाएं वंदनीय रही है। एड्स जैसी बड़ी चुनौती से लड़ने हेतु ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जागरूकता के लिए काफी काम हुआ है। सभी जरूरतमंद बच्चों को समय पर पोलियो का आवश्यक खूराक मिल जाए, इसकी चिंता भी इनके एजेंडे में रही है। इन कार्यों में अदिथि को सरकारी एजेंसियों के साथ ही कुछ व्यक्तिगत और अन्य कई संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलती रही है।

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

निष्कर्ष:

इस तरह के कार्यों एवं एक गैर सरकारी संस्था द्वारा ग्रामीण बिहारी समाज के बीच काम कर महिलाओं के हर क्षेत्र के लिए आगे बढ़ना निःसंदेह बड़ा काम है और इन्होंने सफलतापूर्वक किया भी है। अदिथि ने बिहार के ग्रामीण विकास के स्तर पर आयी तमाम समस्याओं और चुनौतियों को समझते हुए उसका तार्किक समाधान पेश किया है। यह एक मॉडल है, जिसपर हर ग्रामीण समाज को काम करना चाहिए। संसाधन के अधिक न होते हुए भी इसने आय के नये नये अवसर और स्रोत विकसित किए, पूंजी निर्माण में मदद हुआ, उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने में सफल हुआ जो समाज की परंपराओं के मकड़जाल में उलझे हुए थे। बिहार के गांवों में हमने ऐसा होते हुए देखा है। उपर के विश्लेषण में जो सार्वजनिक क्षेत्र या सामाजिक गैर सरकारी संस्थाओं की सीमा पर हमने जो विमर्श को देखा है, उनके सही होने के बावजूद अदिथि के इन कार्यों के प्रति हमें इमानदार होना ही चाहिए। हेबरमास, नैंसी फ्रेजर, बेरेफ्ट, नीरा चंडोक जैसे विद्वानों की सैद्धांतिक समीक्षा के उपर विजी श्रीनिवासन के सफल प्रयोग पर हमें जरूर ही लिखना और बोलना भी चाहिए। हमें याद है कि हेबरमास के सार्वजनिक क्षेत्र के जिस भाषायी सीमा की बात प्रो नीरा चंडोक करती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने समय में अपने ही विद्यार्थियों के प्रति भाषा को लेकर कितना अधिक भेदभाव में शामिल रहीं हैं। हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। भाषायी भेदभाव के प्रति इनकी इमानदारी को हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर, चेन्नई की रहने वाली विजी श्रीनिवासन को बिहार के ग्रामीण समाज में काम करने में कितनी अधिक भाषायी समस्याओं से जूझना पड़ा होगा, फिर भी इन्होंने वह काम कर दिखाया जो केवल विचारों के प्रणेता और कलम के सौदागर ऐसा सोच भी नहीं सकते।

संदर्भ:

- *आरिजनली एपियर्ड इन फिशर लेक्सीकन, स्टैट एंड पालिटिक, न्यू एडिशन (फ्रैंकफर्ट एम मैन, 1964), पृ.220-26*
- *हाउजर, गेराड (1998)' वर्नाकुलर डायलाग एंड द रेट्रोकली आफ पब्लिक अपिनियन, कम्यूनिकेशन मोनोग्राफ्स 65(2): 83-107, पृ.86.*
- *फ्रैजर, नैंसी(1990)' रिथिंकिंग द पब्लिक स्फेयर: ए कन्ट्रीब्यूसन टू द क्रिटिक आफ एक्चुअली एक्झिस्टिंग डेमोक्रेसी, सोशल टेक्स्ट(ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस) 25(26): 56-80,*

आल्सो इन इलियोट, कैरोलिन एम(2003)' सिविल सोसायटी एंड डेमोक्रेसी: ए रीडर(एडिटेड), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 89-105

- *एसेन, रोबर्ट(1999)' टूवार्ड्स ए नारमेटिव कनसेप्सन आफ डिफरेंस इन पब्लिक डेलीबेरेशन, आर्गूमेन्टेशन एंड एडवोकेसी 25(विन्टर), पृ. 115-29*
- *हेबरमास, जर्गेन(जर्मन, 1962, इंग्लिश ट्रांसलेशन, 1989)' द स्ट्रक्चरल ट्रांसफार्मेशन आफ द पब्लिक स्फेयर: एन इन्क्वायरी इनटू अ कैटेगरी आफ बुर्जुवाजी सोसायटी, थोमस बर्गर, कैम्ब्रिज मासाचूसेट्स: द एम आई टी प्रेस, पृ. 30.*
- *चंडोक, नीरा(2003)' द कनसीट्स आफ सिविल सोसायटी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 26.*
- *वारेन, मार्क ई(2000)' डेमोक्रेसी एंड एसोसिएशन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 5-6.*
- *टाकविल, ए (1969)' डेमोक्रेसी इन अमेरिका, टू वोल्यूम्स, गार्डेन सिटी, न्यूयार्क, डबलडे, पृ. 516.*
- *पार्संस, टैलकोट(1971)' द सिस्टम आफ माडर्न सोसायटिज(इंगलवुड क्लिफ्स, एन जे, प्रेक्टिस हाल, पृ. 24,92-98.*

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- चंडोक, नीरा(2009)' पुटिंग सिविल सोसायटी इन इट्स प्लेस, इकानॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी 14, (44),7, पृ.12-16.
- महाजन, गुरप्रीत (1999)' सिविल सोसायटी एंड इट्स अवतार्स, व्हाट हैपंड टु फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? इकानॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,(34),20 मई, पृ.1188-96.
- गुप्ता, दिपांकर(2003)' सिविल सोसायटी आर द स्टेट, व्हाट हैपेंड टू सिटिजनशिप?, इन द एडिटेड बुक आफ कैरोलिन एम (2003)' सिविल सोसायटी एंड डेमोक्रेसी: ए रीडर(ड), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 212.
- मेहता, शिव(1984)' रूरल डेवलपमेंट: पालिसिज एंड प्रोग्राम्स, ए सोशियोलाजिकल पर्सपेक्टिव, सेज पब्लिकेशन, न्यू डेल्ही.
- प्रसाद, युवराज देव एंड मिश्रा, अनिल(2000)' रूरल डेवलपमेंट इन बिहार: प्रोब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव (एडिटेड), हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू डेल्ही.
- रतन, नील(2000)' रोल आफ वोलेन्टरी आर्गेनाइजेशन्स इन रूरल डेवलपमेंट इन बिहार,- प्रसाद, युवराज देव एंड मिश्रा, अनिल(2000)' रूरल डेवलपमेंट इन बिहार: प्रोब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव (एडिटेड), हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू डेल्ही.
- साहू, गोपाल कृष्ण(2000)' वोलेन्टरी आर्गेनाइजेशन्स फोर रूरल डेवलपमेंट, इन कुरूक्षेत्र, जून.
- श्रीनिवासन, विजी (2000)' वुमेन्स इंटिगरेशन इनटू रूरल डेवलपमेंट इन बिहार- ए नोट, रूरल डेवलपमेंट इन बिहार,- प्रसाद, युवराज देव एंड मिश्रा, अनिल(2000)' रूरल डेवलपमेंट इन बिहार: प्रोब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव (एडिटेड), हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू डेल्ही.
- यादव, डी पी(2000)' रुरल डेवलपमेंट इन बिहार: एन ओवरव्यू, इन रूरल डेवलपमेंट इन बिहार,- प्रसाद, युवराज देव एंड मिश्रा, अनिल(2000)' रूरल डेवलपमेंट इन बिहार: प्रोब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव (एडिटेड), हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू डेल्ही.

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies